

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-स्था०1/आ०2-04/2015/ 01

पटना, दिनांक: 01.01.18

कार्यालय आदेश

श्री नदकिशोर जायसवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बखरी प्रखंड, जिला-बेगूसराय संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, महुआ प्रखंड, वैशाली के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 225304 दिनांक 24.03.2015 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 131/आ०प्र०दिनांक 02.02.2015 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०-111 सहपठित ज्ञापांक 687 दिनांक 05.06.2015 द्वारा श्री नंद किशोर जायसवाल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच) बेगूसराय को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगूसराय को नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच) बेगूसराय के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपने पत्रांक 18/वि०जॉच, दिनांक 26.05.2017 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निष्कर्ष दिया है कि "अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय सूखा के कारण सर्वे का कार्य किया जाना था उस समय पदास्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया।

जिस समय आवंटन प्राप्त हुआ उस समय श्री नंद किशोर जायसवाल सर्वे का कार्य नहीं करा सकते थे इसलिए प्राप्त आवंटन का भुगतान लाभुकों के बीच करना संभव नहीं था। इसलिए मजबूरन प्राप्त आवंटन को बिना खर्च किये श्री नंद किशोर जायसवाल के द्वारा सरकार को वापस करना पडा इसके लिए श्री नंद किशोर जायसवाल दोषी नहीं है।

इस प्रकार इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।"

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1772 दिनांक 09.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापांक 1469/राजस्व, दिनांक 18.12.2017 के द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है जो निम्नवत है -

" संचालन पदाधिकारी का मतव्य है कि अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय सूखा के कारण सर्वे का कार्य किया जाना था एवं पूरी प्रक्रिया कर भुगतान हेतु अभिलेख तैयार किया जाना था उस समय पदास्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा यह कार्य नहीं

किया गया। जिस समय आवंटन प्राप्त हुआ उस समय श्री नंद किशोर जायसवाल सर्वे का कार्य नहीं करा सकते थे इसलिए प्राप्त आवंटन का भुगतान लाभुकों के बीच करना संभव नहीं था। इसलिए मजबूरन प्राप्त आवंटन को बिना खर्च किये श्री नंद किशोर जायसवाल के द्वारा सरकार को वापस करना पडा। इसके लिए श्री नंद किशोर जायसवाल को दोषी मानना उचित नहीं होगा।

वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010) में सूखा पडा। उस समय सूखा का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण आवंटित राशि बिना व्यय वापस हो गई। आरोपी श्री जायसवाल, बखरी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में दिनांक 30.08.2011 को योगदान किए। अपेक्षित आवंटन उन्हें बाद में प्राप्त हुआ। जिसे बिना जांच के वितरित करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में श्री जायसवाल के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने संबंधित संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ।”

अतः संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), बेगूसराय द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन एवं उस जांच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री नंद किशोर जायसवाल पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/—

निदेशक

शापाक :- स्था०1/आ०2-04/2015 ०1 पटना, दिनांक ०1.०1.18
प्रतिलिपि :- सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

- 2 जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/वैशाली।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बेगूसराय/वैशाली।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ, वैशाली।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 6 श्री नंद किशोर जायसवाल, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, महुआ प्रखंड, वैशाली

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

१५३२
०१.०१.१८

निदेशक